ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

प्रदूषण से महासागरों पर दोहरी मार

रविवारीय, 03 - 09 अक्टूबर 2021 वर्ष- तीन, अंक -08, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः5 रूपये

बिना टाइगर के टाइगर प्रोजेक्ट?

मनोज कुमार शर्मा

झारखंड अलग राज्य बनने पर किसी गायक ने नागपुरी भाषा में एक मोहक गीत गाया था....

हाय रे हमर नावा राज हाय रे हमर झारखंड, कतइ सुंदर लागे रे

इस वीडियो गीत की एक खास बात थी कि इसके साथ राज्य की प्राकृतिक खुबसूरती के मनोहारी दृश्य भी चलते थे। जिसमें बेतला नेशनल पार्क के घने वनों और उसमें विचरण करते बाघ को भी दिखाया गया था। यह देख कर तब आम झारखंडियों को अपने राज्य के प्राकृतिक समृद्धि, सुंदरता पर गर्व की अनुभूति होती थी। इस गीत को बने आज दो दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्यों, की एक दुखद तस्वीर हमारे सामने है। हकीकत में हमने अपने जंगलों वन्य जीवों को सहेजा नहीं उल्टे इसे बर्बाद किया है।

झारखंड में जहां मुख्यमंत्री इकोटूरिज्म को विकसित करने की बात कहते हैं वहां के लिये नेशनल पार्क किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। लेकिन एक ताजा वाकये में यह पता चला है कि यहां पलामू टाइगर प्रोजक्ट में बाघ नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल दशको पहले राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का भी हुआ था। जब कई सालों तक वहां बाघ नहीं दिखे और बाघ संरक्षण के नाम पर लूट होती रही। अब सवाल उठ रहे हैं कि पलामू टाइगर प्रोजक्ट में बाघ हैं भी या नहीं ?वास्तव में संबंधित अधिकारियों ने गंभीरता से काम किया ही नहीं। तभी तो कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर टाइगर ही नहीं तो टाइगर प्रोजक्ट नाम कैसे?

करोड़ो रूपये खर्च लेकिन जंगलों में मात्र पांच बाघ, एक शाही और सिर्फ छह जंगली कुत्ते

राज्य में जंगलों और वन्य जीवों की संख्या पर क बहुत ही हतप्रभ करने वाली जानकारी सामने आयी है। झारखंड हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद सुनवाई में यह निराश करने वाला आंकड़ा सामने आया कि कुल भूमि के 33 प्रतिशत वनक्षेत्र वाले झारखंड के जंगलों में महज पांच बाघ है। जिसमें वन अधिकारी यह नहीं जानते कि उसमें कितने नर और कितने मादा हैं। वैसे ही भारतीय जंगली कुत्ते जिसे ढोल भी कहते हैं उनकी संख्या मात्र 6 है, कांटेदार जंगली चूहा जिसे शाही या प्रोकोपाइन कहते हैं उसकी संख्या तो सिर्फ एक है और एक हजार से भी कम संख्या लंगूरों की है।

कोर्ट ने फटकार लगाते हुये वन अधिकारियों से कहा कि लाखो करोड़ो रूपये वन्य जीवों के संरक्षण पर खर्च हो रहे हैं तो फिर वन्य जीवों की संख्या इतनी कम क्यों है ?चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिग से हुयी इस सुनवाई में वन सचिव , पीसीसीएफ हेड ऑफ फोर्स और चीफ वाइल्ड वार्डेन कोर्ट के सवालों पर बंगले झांकते नजर आये। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुये कहा कि जब पलामू टाइगर प्रोजेक्ट में बाघ ही नहीं तो टाइगर प्रोजेक्ट नाम किस लिये? इसका नाम क्यों नही बदल दिया जाये? कोर्ट ने कहा है कि अन्य जगहों से वन्य जीवों को लाकर जंगलों में इनकी संख्या बढायें। हाथियों की मौत पर भी कोर्ट ने चिंता व्यक्त की और कहा कि जानवरों के 80% मौत के मामलों में फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आती

सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है बेतला

1974 में स्थापित भारत के सबसे पुराने टाईगर रिजर्व में से एक बेतला राष्ट्रीय पार्क है जिसे पूर्व में पलामू टाईगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। यहां बड़ी संख्या में बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, बंदर, सांभर, नीलगाय, मोर और चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं।

कभी देश विदेश के वन्यप्रमियों का यह पसंदीदा अभयारण्य था। दशकों पहले दूरदर्शन ने जब देश भर के बाघ अभयारण्यों पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया और प्रसारित किया था तब बेतला को उसमें सबसे समृद्ध बताया गया था। आज बहुत ही अफसोस की बात है कि यहां का वन्य जीवन सिकुड़ गया है और अब बाघ पता नहीं दिखते भी हैं या नहीं? झारखंड जैसे राज्य के लिये यह स्थिति बहुत बड़ी क्षति है।

बेतला नेशनल पार्क पर पर हमेंशा रहा है संकट

दशकों पहले पलामू में भयंकर सूखा पड़ा था तब इसका असर बेतला नेशनल पार्क के वन्य जीवों पर भी पड़ा था। तब अभ्यारण्य के प्यासे हिरण पानी की तलाश में गावों तक आ जाते थे और लोगों को पानी ढोते देख प्यासे जानवर उनके पास मंडराते थे। उस समय इनका भरपूर अवैध शिकार हुआ था। अब मंडल डैम के निर्माण में भी पार्क के लाखो पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ महिनों पहले वनकर्मियों की लापरवाही से यहां के एक पालतू हाथी कालभैरव को जंगली हाथियों ने मार डाला था। एक बाघ का शव भी मिला था जिसकी जांच का कुछ पता नहीं।

झारखंड में अभ्यारण्य

झारखंड प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य रहा है. यहां के वनों में भेड़िया, गौर, हाथी, तेंदुए आदि पाए जाते रहे हैं. वन्य जीव संरक्षण के लिये यहां एक राष्ट्रीय उद्यान और तकरीबन 11 अभयारण्य है. लेकिन कुछेक को छोड़ कर ज्यादतर की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। महुआ डाड़ में राज्य का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1976 में की गयी थी और यह 63 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यहां आज भी भेड़ियों की संख्या सीमित है। ऊपर से घटते वनों और अतिक्रमण के कारण इन पर भी संकट है।

इन अभ्यारण्यों को बचाने और सहेजने के नाम पर अरबों रूपये फूंके जाते हैं, पर वन्य जीवों की संख्या सिमटती ही जा रही है।

गांधी जयंती के अवसर पर छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान (सर्वोदय आश्रम), तिरिल, ची स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन।

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

खेती की तरह बिजली की भी खेती करें:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है । उन्होंने लोगों से कहा कि वे खेती की तरह बिजली की भी खेती करें। अपनी बंजर भूमि और घर की छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करे । इससे ना सिर्फ अपने लिए बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, बल्कि सरप्लस बिजली को सरकार खरीदेगी । इससे आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा होगा और आप राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी । इसके लिए बहुत जल्द एक नई योजना लांच की जाएगी ।

एक अक्टूबर से देश को कूड़ामुक्त बनाने के लिये एसबीएम-यू 2.0 की शुरूआत

शहरी भारत सेजाना करीब 0.15 टन मिलियन ठोस कचरा पैदा करता है, जिसमें से केवल 68 फीसद नष्ट करने के लिए इकट्ठा किया जाता है

देश के सभी शहरों को कूड़ामुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन - शहरी, यानी एसबीएम-यू 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत 2.0 को हरी झंडी भी दिखाएंगे।

भारतीय शहरों को कूड़ामुक्त करने और खुले में शौचमुक्त बनाने के अभियान एसबीएम-यू 2.0 पर लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, 'इस मिशन का उद्देश्य ठोस कचरे के स्रोत पृथक्करण पर फोकस करना है। इसके लिए तीन आर, यानी रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल का उपयोग कर वैज्ञानिक पद्धति से सभी तरह के शहरी ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए पुराने कचरे के मैदानों को भी दुरुस्त किया जाएगा। आबादी के बढ़ने और शहरीकरण के तेज होने के चलते देश के शहरों में ठोस कचरे के विस्फ़ोट हुआ है। इसने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला है। इसके चलते शहरों के स्थानीय निकायों की ठोस कचरे को एकत्र करने, उसे ले जाने, संभालने और उसका निस्तारण करने की क्षमता प्रभावित हुई है।

वेस्ट टू एनर्जी रिपोर्ट, 2014 में अनुमान लगाया गया था कि अप्रयुक्त कचरे में 439 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। कचरे की 32890 टन प्रति दिन मात्रा में ज्वलशील पदार्थ और अस्वीकृत ईंधन या आरडीएफ शामिल होता है। इस कचरे से हर रोज 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस तैयार की जा सकती है और उस बायोगैस से भी 72 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। इस कचरे से खेती में इस्तेमाल होने वाली 5.4 मिलियन मीटरी टन खाद सालाना तैयार की जा सकती है। देश के कई हिस्सो में कचरा एक़त्र करने और उसे रिसाइकिल का काम प्रभावी तरीके से नहीं किया जाता। उद्योगों, निकायों, खेती, निर्माण-स्थलों, तोड़-फोड़ वाली और अन्य जगहों से निकलने वाले कचरे को कबाड़ जैसे लोहे के चीजें, प्लास्टिक आदि में अलग किया जा सकता है। इसके बाद उनका रिसाइकिल कर बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। यह हालत तब है जब देश में रिसाइक्लिंग की दरें दुनिया के मानकों की तुलना में काफी कम हैं।

सीसीएल मुख्यालय रांची में गांधी जयंती मनाई गई

संवाददाता, रांची : सीसीएल मुख्यालय रांची में महात्मा गांधी और लाल बहादरु शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कंपनी के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों के भी इसका आयोजन किया गया।

रांची में कार्यक्रम की शुरुआत सीएमडी, सीसीएल पी.एम प्रसाद ने महात्मा गांधी और लाल बहादरु शास्त्री की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर बोलते हुए सीएमडी ने कहा कि महात्मा गांधी के

आदर्श शाश्वत हैं और हम सबको उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनका स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत रत्न लाल बहादरु शास्त्री सादगी और सत्यनिष्ठा के प्रतिमूर्ति थे और सभी को उनसे प्रेरित होकर इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञात हो कि अक्टूबर के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सीसीएल में विभिन्न कार्यक्रम आयोति किए जा रहे हैं।

द.पू.रेलवे महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने किया हटिया स्टेशन पर इफ़्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन

संवाददाता

रांची : दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने रांची रेल मण्डल का दौरा किया। इस दौरान उन्होने रांची स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं यथा फूड स्टाल , नव निर्मित फूट ओवर ब्रिज , कम्प्यूटरीकृत पैनल , प्रतीक्षालय एवं रांची स्टेशन पर स्थित विभिन विभागों के कार्यालयों का वृस्तृत निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता और यात्री सुविधा के प्रति संतुष्टि व्यक्त की और जहां सुधार करने की आवश्यकता है वहां सुधार करने के निर्देश भी दिए । निरीक्षण के दौरान मुख्यालय से आए सभी विभागाध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता एवं मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।इसके बाद उन्होंने हटिया में स्काउट तथा गाइड द्वारा आयोजित स्वच्छता जागरूकता रैली को झण्डा दिखाकर रवाना किया। उन्होने पर्यावरण संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया और हटिया स्टेशन पर प्रतिदिन 500 किलोलीटर अपशिष्ट पानी को शोधन करने की क्षमता वाले ई टी पी (इफ़्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) का उदघाटन किया इसके द्वारा हटिया स्टेशन एवं कोचिंग डिपो के अपशिष्ट पानी को शोधन कर पुनः प्रयोग किया जा सकेगा ।

झारखंड में उद्यानिकी को रोजगारपरक बनाने का प्रयास

मुरलीधर

- **उद्यानिकी बनेगा आधार, मिलेगा रोजगार**
- **सरकार का है प्रयास, कृषि का हो चौमुखी विकास**
- **कृषकों को उद्यानिकी, फूल, मशरूम, सब्जी, स्ट्राबेरी के उत्पादन का मिलेगा प्रशिक्षण, बढ़ेगी आय**

उद्यानिकी को स्वरोजगार का आधार बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की ओर से बजट भी निर्धारित किया गया है। किसानों, युवाओं और महिलाओं को उद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं के तहत विभिन्न तरह के प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम हैं। योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों का बहुमुखी विकास एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना है। साथ ही उद्यानिकी के लिए अनुकूल झारखण्ड के मौसम, मिट्टी और पारिस्थितिकी का लाभ राज्यवासियों को देना है।

इन क्षेत्रों में मिलेगा प्रशिक्षण

राज्य के सभी जिलों में उद्यानिकी फसलों के बहुमुखी विकास हेतु पंचायत स्तर पर चयनित बागवानी मित्रों, प्रखंड स्तर पर कार्यरत उद्यान मित्रों और कृषकों को उद्यानिकी फसलों की तकनीकी खेती से संबंधित जानकारी के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण के दौरान मिलनेवाला भत्ता, भोजन, आने-जाने, ठहरने व प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

शहरी क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा माली का प्रशिक्षण : योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के युवाओं को माली का प्रशिक्षण भी दिया जाना है। इससे जहां शहरी क्षेत्रों में बागों, पार्कों के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं युवा आत्मनिर्भर भी होंगे। यह प्रशिक्षण राज्य सरकार और भारत सरकार के चिह्नित संस्थानों या एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से होगा। माली का निःशुल्क प्रशिक्षण 25 दिन का होगा।

मिर्च और मशरूम की खेती का प्रशिक्षण

मिर्च व मशरूम की खेती को बढ़ावा देना भी पहल का हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत आनेवाले 13 जिलों रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पाकुड़, लातेहार के 420 हेक्टेयर, क्षेत्रीय योजना के तहत हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गोड्डा, चतरा, धनबाद, पलामू एवं बोकारो सहित 11 जिलों के 210 हेक्टेयर एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, कोडरमा, गढ़वा, धनबाद पलामू एवं बोकारो सहित 11 जिलों में 700 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च की खेती को बढ़ावा देने की योजना है। साथ ही मशरूम उत्पादन के लिए सभी जिलों के कृषकों को नई तकनीक से पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

खुले वातावरण में फूल और पपीता की खेती को बढ़ावा

कृषक फूलों की खेती के लिए प्रेरित हों, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में चयनित स्थलों पर फूल की खेती की जायेगी। राज्य में कुल 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूल की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। पपीता को पौष्टिक फलों की श्रेणी में रखा जाता है। पपीता की खेती को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इससे जहां किसानों की आय में वृद्धि होगी, वहीं ग्रामीणों को भी पौष्टिक फल सुलभ होगा। सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब आठ लाख पपीते के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पपीता पौध उत्पादकों के माध्यम से पौधा उपलब्ध कराया जायेगा। जो किसान खुद पपीते का पौधा तैयार करेंगे, उन्हें भी सरकार विशेष अनुदान राशि देगी।

इसी तरह से कृषकों को टिश्यू कल्चर, स्ट्राबेरी, पॉली हाउस निर्माण, सब्जी की खेती, गृह वाटिका की स्थापना आदि को भी प्रशिक्षण से जोड़ने की योजना है। इस प्रशिक्षण से युवाओं और कृषकों को काफी लाभ होगा। जहां एक ओर वे आधुनिक तरीके से उद्यानिकी के बारे जानेंगे, वहीं राज्य भी फलों, सब्जियों के मामले में और अधिक आत्मनिर्भर होगा।

हमारे युवा इतने कमजोर क्यों?

30 सितंबर को रांची में एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा ने अपने अपार्टमेंट के छत से कूद कर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसके परिजन इसे आत्महत्या नहीं मान रहे हैं और पुलिस जांच चल रही है। वहीं सरायकेला में एक युवक अपने पिता की मृत्यु से इतना आहत था कि उसने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। दोनों ही वाकये बहुत ही हृदयविदारक हैं।

क्या हमारा आज का युवा दबावों और संघर्षों के सामने हार जा रहा है? हम लाख किसी इक्के दुक्के के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रकाशित कर उसे नजीर बना कर पेश करें, पर यह हकीकत है कि आज समाज में महात्वाकांक्षा के हद से ज्यादा बढ़ने, बेकार की आपसी स्पर्द्धा,इर्ष्या और अन्य मानसिक कारणों से युवाओं पर बहुत ज्यादा सफलता का दबाव है।

इन सबके इतर किसी भी कारण से उपजने वाला अवसाद सबसे खतरनाक है। यह संपन्न से लेकर मध्यवर्ग यहां तक की गरीब तबके को भी अपने चपेट में ले रहा है।आज जबकि पहले की अपेक्षा समृद्धी आयी है, अब पहले की तरह अकाल, भुखमरी जैसी स्थिति नहीं है, बाजार के इस नये दौर में किसी भी परिश्रमी व्यक्ति के लिये कोई रोजगार पाना, कमाना और अच्छे से जीवनयापन करना कोई मुश्किल काम नहीं, फिर भी देश में खासकर युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृति बहुत ही चिंताजनक है। निश्चय ही सुकूनदेह प्रकृति से दूरी, शहरों में मानसिक अशांति के साथ ही आधुनिक बेतरतीब रहन सहन और वर्तमान का एकल और अपार्टमेंटों का कम सामाजिक और एकाकी रहन सहन लोगों को अंदर से कमजोर बना रहा है। मनोचिकित्सक भी कहते हैं आज का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि किसके अंदर कितना तनाव और अवसाद भरा हुआ है उसे हम ऊपर से देख कर नहीं समझ सकते, एक आम खुशमिजाज सा दिखने वाला व्यक्ति भी मन ही मन आत्महत्या की ओर अग्रसर रहता है।

> आज जब चहुंओर भोग विलास के नये-नये भौतिक साधन है, गरीब होने का पुराना पैमाना बदल चुका है, अब गरीब के घर में भी ढेर सारी सुख सुविधायें है, बाजार ने रोजगार और कमाने के नये -नये अवसर पैदा किये हैं, फिर भी युवाओं में आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं।

इसके निदान के लिये तो अंततः परिवार, समाज को ही आगे आना होगा। एकल परिवार, बुजुर्गों से दूर रहने वाले युवा, अपने अपने काम में लगा किसी दूसरे की सुध न लेने वाला समाज, प्रकृति और शांति से दूर शहर के कहर में फंसा युवा मामूली से मानसिक संकट को नहीं झेल पा रहा तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो हमारा रहन सहन सोच और समाज ही है।

तापमान को कम करते हैं पौधों से बने एरोसोल

प्राकृतिक एरोसोल जलवायु के गर्म होने को धीमा कर सकते हैं

एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में महीन ठोस कणों या तरल बूंदों का मिश्रण है। एरोसोल प्राकृतिक या मानवजनित हो सकते हैं। एरोसोल कण पृथ्वी में सीधे सौर विकिरण या सूरज के प्रकाश को रोक कर प्रभावित करते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से बादलों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए जलवायु प्रणाली में कार्बनिक एरोसोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

फिनिश शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वनस्पति द्वारा उत्सर्जित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वायुमंडलीय एरोसोल बनाते हैं जो बादलों को अधिक चमकदार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चमकीले बादल पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे सतह ठंडी हो जाती है। बढ़ते तापमान के साथ वनस्पति से कार्बनिक यौगिकों का उत्सर्जन बढ़ता है, इस प्रकार जलवायु में बढ़ती गर्मी धीमी हो जाती है। वायुमंडलीय एरोसोल सूरज के प्रकाश को बिखेरते हैं और अवशोषित करते हैं और इस तरह बादलों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अवलोकनों से पता चला है कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से बनने वाले बॉयोजेनिक एरोसोल ने अंतरिक्ष में अधिक विकिरण को बिखेर कर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम कर दिया है। यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है इसके अलावा, इन एरोसोल ने बादल की बूंदों की मात्रा में वृद्धि की और बादलों को अधिक परावर्तक बना दिया। तापमान बढ़ने पर दोनों प्रक्रियाओं में इजाफा होता है, यह दर्शाता है कि ये प्राकृतिक एरोसोल जलवायु के गर्म होने को धीमा कर सकते हैं।

समुद्र के सतही पानी में तीन गुना से अधिक बढ़ा पारा

दुनिया भर में उद्योगों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा गया पारा समुद्र में प्रवेश करता है। वायुमंडल में अकार्बनिक पारा (एचजी) का मानवजनित उत्सर्जन प्राकृतिक उत्सर्जन से पांच से दस गुना अधिक है। इस तरह सतही समुद्र के पानी में अकार्बनिक पारे (एचजी) की मात्रा तीन गुना से अधिक बढ़ गई है। समुद्र में जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन ने मछलियों में मोनो मिथाइल पारा के स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि भविष्य में पारे से इंसानों पर होने वाले खतरों का आकलन करने के लिए विस्तृत मॉडल की आवश्यकता है।

अब बेसल विश्वविद्यालय के एक विश्लेषण के द्वारा पता लगाया गया है कि हानिकारक पदार्थ सबसे पहले समुद्र के पानी में किस तरह प्रवेश करते हैं। पहले माना गया था कि वातावरण में जारी पारा मुख्य रूप से वर्षा के माध्यम से समुद्र में प्रवेश कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें गैसों में बदलाव भी शामिल है।

बिहार सरकार के पास नहीं हैं पर्याप्त आंकड़े कैसे बनेगा क्लाइमेट एक्शन प्लान?

उमेश कुमार राय

साल 2015 के क्लाइमेट एक्शन प्लान को केंद्र सरकार ने ये कहकर वापस कर वापस कर दिया था कि एक्शन प्लान में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क्या कार्य-योजना है, इसका जिक्र नहीं है। अब बिहार सरकार पिछले 10 साल के आंकड़ों के आधार पर नये सिरे से क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए पंचायत स्तर पर आंकड़े जुटाए जाने है पर अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि विभिन्न विभागों से आंकड़े नहीं मिल रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 2002 में जैव-विविधता से संबंधित रजिस्टर तैयार करने की नीति बनाई थी। एनजीटी के आदेश के बाद भी बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस नीति का सही से पालन हुआ रहता तो आज आंकड़ों से संबंधित ऐसी चुनौती नहीं आती। विकास के विभिन्न मानकों पर बिहार जैसे राज्य की स्थिति जगजाहिर है। वर्तमान समय की नई चुनौतियों से निपटने में भी यह राज्य फिसड्डी साबित हो रहा है। ताजा मामला है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौती का। राज्य के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने की कोशिश हो रही है पर विडंबना यह है कि इसके लिए जो आंकड़े चाहिए वह मौजूद नहीं है। गौरतलब हो कि बिहार सरकार ने साल 2015 में ही क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन उसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को लेकर कोई कार्य-योजना शामिल नहीं थी। इस वजह से साल 2019 में बिहार सरकार ने इसे वापस ले लिया था।

इसी साल बिहार सरकार ने इसके बाद अब राज्य सरकार दोबारा क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत बिहार सरकार ने इसी साल 12 फरवरी को यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। बिहार में 2019 में गठित क्लाइमेट चेंज विंग के नोडल अधिकारी एके द्विवेदी ने बताया, कि क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार करने के लिए जलवायु जोखिम के मूल्यांकन (क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमलोगों ने जोखिम मूल्यांकन के बाद क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार कर लेने के लिए दो साल का समय मांगा है। अगर केंद्र सरकार हमारे प्लान को हरी झंडी दे देती है, तो हम उसी के अनुरूप बिहार में अडेप्टेशन या मिटिगेशन पर काम करेंगे, जोखिम मूल्यांकन ब्लॉक और पंचायत स्तर पर होगा। इसी के आधार पर पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

साल 2015 में बिहार सरकार की तरफ से तैयार किये गये क्लाइमेट एक्शन प्लान (जिसे केंद्र सरकार वापस कर चुकी है) के अध्ययन में पाया कि 10 सालों का आंकड़ा पंचायत स्तर पर दूर, जिला स्तर पर भी मिलना लगभग असंभव है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर बताया, ''पंचायत और ब्लॉक स्तर का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। हमारी अपनी केवल चार ऑब्जर्वेटरी है- पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में। ये काफी पुरानी है इसलिए इन चार जिलों के 10 साल के मौसम के आंकड़े मिल सकते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन्स बहुत बाद में लगे हैं। इसके अलावा बिहार में 250 रेन गॉज लगे हुए हैं। किसी जिले में पांच रेन गॉज हैं, तो वहां की पांच जगहों का ही बारिश का आंकड़ा मिल सकता है।''

आंकड़े न होने का नुकसान

दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉ प्रधान पार्थ सारथी ने बताया,कि अगर सरकार ये कह रही है कि वह ब्लॉक और पंचायत स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार करेगी, तो ऐसा करना असंभव है। जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए मुख्य तौर पर बारिश और तापमान के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास पंचायत तो दूर हर ब्लॉक का तापमान और बारिश का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में प्लान कैसे तैयार होगा? ''अगर एक अनुमान के आधार पर प्लान तैयार किया जाता है, तो वह प्रभावशाली नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां एक जगह बारिश होती है, तो कुछ किलोमीटर दूर बारिश नहीं होती है। । नवंबर, 2019 में सरकार ने जलवायु संकट का सामना करने में सक्षम नये फसल चक्र की शुरुआत की। सरकार का दावा है कि इस नये फसल चक्र को अपनाकर राज्य के किसान जलवायु संकट का सामना कर पाने में सक्षम होंगे और मौसम के अप्रत्याशित बदलाव से सुरक्षित रहेंगे।' आंकड़े न हो तो जोखिम मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल होगा। सटीक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। ऐसे में अभी जिस स्तर पर आंकड़े उपलब्ध हैं, उसी स्तर से जोखिम मूल्यांकन शुरू करना चाहिए। लेकिन साथ ही अभी से सभी तरह के आंकड़ो को सहेजना शुरू कर देना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न हो।

जैव-विविधता प्रबंधन समिति को लेकर ढिलाई बरतने की कीमत

देश में 2002 में ही एक नीति बनाई गयी थी और बिहार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। नहीं तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। भारत सरकार ने साल 2002 में जैविक विविधता अधिनियम बनाया था, जिसका उद्देश्य था पंचायत स्तर पर मौजूद जैव-विविधताओं का रजिस्टर तैयार करना और उन्हें संरक्षित रखते हुए उनके जरिए आजीविका का जरिया मुहैया कराना। इसके तहत साल 2003 में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण का भी गठन हुआ था। इसके बाद सभी राज्यों में राज्य जैव-विविधता बोर्ड का गठन हुआ। जैव-विविधताओं का रजिस्टर तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर निकाय (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र) में सात सदस्यीय जैव-विविधता प्रबंधन समिति बनाने का आदेश था, जिन्हें ट्रेनिंग दी जानी थी। ये समिति ही जैव-विविधताओं को लेकर रजिस्टर तैयार करती और उसे राज्य जैव-विविधता बोर्ड को मुहैया कराती। अगर इस पर गंभीरता से काम हुआ होता तो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने के लिए पंचायत स्तर पर बहुत मजबूत आंकड़े मिल जाते। इसको लेकर बिहार सरकार की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रायबुनल (एनजीटी) की तल्ख टिप्पणी के बावजूद बिहार सरकार का कदम बेहद सुस्त रहा है। 9 अगस्त 2019 को एनजीटी ने अपने आदेश में कहा, ''बिहार और जम्मू-कश्मीर में जैव-विविधता प्रबंधन समिति बनाने की दिशा में शून्य प्रगति हुई है।

एनजीटी ने बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 31 जनवरी 2020 तक जैव-विविधता प्रबंधन समिति बनाकर जैव-विविधता रजिस्टर तैयार करने का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लेने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया था।तब एनजीटी को दिखाने के लिए बिहार सरकार ने जल्दबाजी में समिति बना ली थी। अब अगर दोबारा एनजीटी जैव-विविधता रजिस्टर तैयार करने को कहेगा, तो इसी तरह जल्दबाजी में सरकार रजिस्टर बनवाएगी, जो जाहिर है तथ्यों पर आधारित नहीं होगा।

तापमान बढ़ने से बढ़ जाएंगे चक्रवाती तूफान 180 करोड़ लोगों पर है खतरे की आशंका

ललित मौर्य

उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहले ही दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं, जिनके चलते पहले ही हर साल करीब 15 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जितना जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे, उनकी मदद से सदी के अंत तक 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को उष्णकटिबंधीय तूफानों का सामना करने से बचाया जा सकता है। इस पर हाल ही में किए एक शोध से पता चला है कि आने वाले कुछ दशकों में जिस तरह से जनसंख्या और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसके चलते पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लोगों को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहले ही दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं। जिनके चलते पहले से हर साल करीब 15 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है। गौरतलब है कि इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। बढ़ती आबादी और तापमान में हो रही वृद्धि ने इस जोखिम को और बढ़ा दिया है। विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीकी देशों और अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में इनसे सबसे ज्यादा खतरा है। अनुमान है कि जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उसके चलते कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों में तूफान का यह खतरा 300 फीसदी और अमेरिका में 100 फीसदी तक बढ़ जाएगा, जबकि अरब प्रायद्वीप में भी यह खतरा पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाएगा। यह जानकारी हाल ही में जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक शोध में सामने आई है।

शोध से पता चला है कि यदि विश्व के औसत तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो इन तूफानों का सामना करने वाले लोगों की संख्या पहले की तुलना में करीब 26 फीसदी बढ़ जाएगी। यह आंकड़ा करीब 3.3 करोड़ होगा। अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक आबादी अपने चरम पर पहुंच जाएगी, उसके बाद इसमें गिरावट आना शुरु हो जाएगी।यादि 2050 तक जलवायु परिवर्तन को कम करने पर विशेष ध्यान न दिया गया तो अनुमान है कि इसके चलते तापमान में हो रही वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगी। जिसके चलते लोगों के इन तूफानों की जद में आने का खतरा करीब 41 फीसदी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि तापमान में हो रही इस वृद्धि के चलते भविष्य में और 5.2 करोड़ लोग इन तूफानों का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे।

वहीं दूसरी तरफ यदि जलवायु में आने वाले बदलावों को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश की जाती है और उसके बाद सदी के अंत तक हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने में कामयाब रहते हैं तो भी इन तूफानों का सामना करने को मजबूर लोगों की संख्या में 20 फीसदी का इजाफा होना तय है, जो करीब 2.5 करोड़ के करीब होगा। ऐसे में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि जलवायु में आ रहे बदलावों को रोकने के लिए अभी ठोस कदम उठाएं गए तो सदी के अंत तक करीब 180 करोड़ लोगों को इन तूफानों से बचाया जा सकता है।

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला था कि पिछले 50 वर्षों में मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही इनसे करीब 266 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें तूफानों से होने वाला नुकसान भी शामिल है।यदि इस अवधि की 10 सबसे विनाशकारी आपदाओं की बात करें तो उनमें उष्णकटिबंधीय तूफान, सूखे के बाद दूसरे स्थान पर थे, जिनमें करीब 577,232 लोगों की जान गई थी, जोकि पिछले 50 वर्षों के दौरान मौसम और जलवायु सम्बन्धी आपदाओं में मारे गए लोगों का करीब 38 फीसदी है। इस रिपोर्ट में भी तापमान में हो रही वृद्धि को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता में हो रही वृद्धि के लिए जिम्मेवार माना है। वहीं यदि तापमान में हो रही वृद्धि की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि इस बात की करीब 40 फीसदी संभावनाएं है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी

2020 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था जब तापमान में हो रही वृद्धि 1.28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी। जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित "एमिशन गैप रिपोर्ट 2020" के अनुसार सदी के अंत तक तापमान में हो रही वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी। ऐसे में उष्णकटिबंधीय तूफानों के बढ़ते खतरे से बचने के लिए यह जरुरी है कि तापमान में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए जितना जल्द हो सके ठोस कदम उठाएं जाएं।

वैज्ञानिकों ने बनाया एआई आधारित फेस मास्क

प्रदूषण के हिसाब से खुद को कर सकता है एडजस्ट

वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमता यानी एआई आधारित ऐसे फेस मास्क को बनाने में सफलता हासिल की है, जो वातावरण में मौजूद प्रदूषण को देखते हुए अपना आप को उसके अनुरूप ढाल सकता है।सॉफ्टवेयर की मदद से इस फेस मास्क में लगा रेस्पिरेटर, लगाने वाले की सांस के पैटर्न और प्रदूषण की मात्रा के आधार पर अपने आप को ढाल सकता है

इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा वक्त में फेस मास्क लोगों की जरुरत का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इस महामारी के दौर में लोग अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए फेस मास्क पहनने के आदी हो चुके हैं। आज जो मास्क उपलब्ध है वो अपने आप को परिस्थितियों के आधार पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं।

इस समस्या को देखते हुए शोधकर्ताओं ने एआई आधारित एक रेस्पिरेटर बनाया है जो वातावरण के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए जब आप स्वच्छ वातावरण में अकेले व्यायाम कर रहे हैं तो उस समय आपको महीन छिद्रों वाले मास्क की जरुरत नहीं रहती। उस समय इसके छिद्र अपने आप बड़े हो जाएंगे, जिससे सांस लेने में आसानी हो। वहीं यदि वातावरण में प्रदूषण को स्तर ज्यादा होगा, तो यह अपने आप छिद्रों को उसके हिसाब से ढाल लेंगें।

यह शोध अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल एसीएस नैनो में प्रकाशित हुआ है।

2020 में पहले से कहीं ज्यादा अमेरिकियों को नहीं मिला पर्याप्त भोजन

अमेरिकी मध्य वर्ग पर पड़ी जबरदस्त मार। भोजन की कमी का सामने कर रहे अमेरिकियों का जो आंकड़ा 23 अप्रैल, 2020 तक साढ़े नौ फीसदी था

झेंग तियान, स्टीफन जे गोएट्ज

कोरोना महामारी ने अमेरिका के मध्यम वर्गीय परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जब इस महामारी ने अमेरिका में अपने पैर पसारने शुरु किए तो सालाना 50 हजार से 75 हजार डॉलर कमाने वाले मिडिल क्लास परिवारों ने बड़ी तेजी से खाद्य पदार्थों की कमी का अनुभव किया था, जिसका मतलब है कि पिछले केवल सात दिनों में इन परिवारों के पास खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यह जानकारी हाल ही में किए एक अध्ययन में सामने आई है जो जल्द ही जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में प्रकाशित होगा।

शोध में यह भी सामने आया है कि फूड बैंक, फूड पैंट्री और इस तरह की आपातकालीन सेवाओं ने 2020 के अंत तक, विशेष रूप से मध्यम आय वाले अमेरिकियों के लिए, खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने मदद की थी। शोधकर्ताओं के अनुसार जब उन्होंने 23 अप्रैल, 2020 के बाद एकत्र किए गए जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों का औसत निकाला, तो पता चला कि अमेरिका में सभी आय वर्गों के बीच खाद्य अपर्याप्तता की दर में वृद्धि हुई है।

इसमें कोई शक नहीं कि सालाना 50,000 डॉलर से कम कमाने वाले अमेरिकी परिवारों में खाद्य पदार्थों की कमी की सबसे ज्यादा सम्भावना है और यह बात महामारी के शुरुआती महीनों में सही भी साबित हुई थी। जब कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्कूल, कार्यालय और रेस्तरां जैसे स्थान कर दिए गए थे। लेकिन अमेरिका में रह रहे वो परिवार जिनकी वार्षिक आय 75 हजार डॉलर से कम हैं उन सभी के लिए अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच खाद्य पदार्थों की कमी सम्बन्धी दरों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई थी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार से 75 हजार डॉलर के बीच थी उनके बीच यह दर सबसे तेजी से करीब आधा फीसदी बढ़ी थी, जो 0.98 फीसदी से बढ़कर 1.48 पर पहुंच गई थी। हालांकि जिन परिवारों की आय 1.5 लाख डॉलर से ज्यादा थी उनमें खाद्य

अपर्याप्तता की दर में कोई खास बदलाव नहीं दर्ज किया गया है। यही नहीं शोधकर्ताओं ने इस बात का भी अलग से अध्ययन किया है कि क्या जिन राज्यों में फूड बैंक और इस तरह की ज्यादा सेवाएं उपलब्ध थी वहां खाद्य पदार्थों की कमी के मामले में कोई फर्क पड़ा था। इस बारे में शोधकर्ताओं को पता चला है कि इन फूड बैंक ने खाद्य पदार्थों की कमी को प्रभावित किया है। जिन राज्यों में प्रति 10 हजार लोगों पर इन संगठनों की संख्या सबसे ज्यादा थी, वहां कीमतों में तेजी से कमी आई थी। यह 50 से 75 हजार डॉलर कमाने वाले परिवारों के लिए मुख्य रूप से सही था।

जब महामारी का दौर शुरु हुआ तो इस बात की पूरी आशंका थी कि इसका असर खाद्य आपूर्ति पर पड़ेगा। साथ ही इस बात की भी पूरी सम्भावना थी कि इस महामारी के चलते पहले से कहीं ज्यादा लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। लॉकडाउन के बाद जब लाखों मजदूरों की छंटनी बहुत छोटे नोटिस के बाद कर दी गई तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। लम्बी-लम्बी कतारों में भोजन सामग्री की प्रतीक्षा करते लोगों की सामने आई तस्वीरों ने इन आशंकाओं को और प्रबल कर दिया था। इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता था, जब खाद्य पदार्थों की कमी का अनुभव करने वाले परिवारों की संख्या पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अमेरिकी कृषि विभाग ने पाया कि खाद्य असुरक्षा का जो आंकड़ा 23 अप्रैल, 2020 तक साढ़े नौ फीसदी था वो 21 दिसंबर, 2020 तक बढ़कर 13.4 फीसदी पर पहुंच गया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस स्थिति से निपटने में फूड बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अमेरिका में खाद्य सुरक्षा के लिए काम कर रहे संगठन फीडिंग अमेरिका के अनुसार इन फूड बैंकों ने करीब 6 करोड़ अमेरिकियों को 2020 में आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करने में मदद की थी। वहीं मध्यम-आय वाले लोगों ने खाद्य बैंकों और इसी तरह के संगठनों से मदद ली थी क्योंकि उन्हें निम्न आय वाले लोगों की तुलना में सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए हो सकता है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम में नाम कैसे दर्ज किया जाता है।

हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा संचालित पोषण कार्यक्रमों की तुलना में खाद्य बैंक और उन जैसे संगठन कितने लागत प्रभावी हैं। चूंकि सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (स्नैप) खुदरा विक्रेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा स्वीकार किए गए एक विशेष प्रकार के डेबिट कार्ड के माध्यम से लाभ वितरित करता है, ऐसे में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त खर्चों की जरुरत पड़ती है।

क्या होगा अगला कदम

शोधकर्ताओं के अनुसार वो वर्तमान में खाद्य पदार्थों की कमी और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों की जांच कर रहे हैं। साथ ही वो यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2021 के अंत और 2022 में जब महामारी से सम्बंधित अल्पकालिक योजनाओं का वक्त पूरा हो जाएगा तो उसका खाद्य असुरक्षा की दर पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही शोधकर्ता उन अन्य कारकों की भी खोज कर रहे हैं जो अलग-अलग राज्यों में खाद्य पदार्थों की दर में कमी सम्बन्धी असमानता के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। **साभार : डीटीई**

चतरा में अफीम की खेती रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम

संवाददाता : मुख्यमंत्री ने कहा कि चतरा समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती होती है । इसे रोकने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं । अफीम की बजाय मेडिसिनल प्लांट्स आदि की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है इससे लोगों की आमदनी में काफी इजाफा होगा । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी लोग अफीम की खेती से जुड़े होंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफीम अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी को इससे दूर रहने की जरूरत है ।

सीएमपीडीआई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनायी गयी

रांचीः सीएमपीडीआई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनायी गयी। इस अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विनय दयाल, निदेशक (तकनीकी/आरड-ीएंडटी)आर0एन0 झा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी/ईएस) एस0के0 गोमास्ता एवं महाप्रबंधक (समन्वय) मनोज कुमार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विनय दयाल ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को पूरी दुनिया मानती है। उनका संघर्षमय प्रेरणादायी जीवन रहा है। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की साधन दोनों के पवित्र होने का पक्षधर रहे।

बीएयू में 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

मोटे अनाज का बाजार मूल्य को बढाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी : डॉ ओएन सिंह

मडुआ के उत्पादों से राज्य में रोजगार के नये आयाम की काफी संभावना : डॉ ए पट्टनायक

संवाददाता

रांची:बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान विभाग का पोषक अनाजों के प्रसंस्करण विषय पर आयोजित दूसरा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन के अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति डॉ ओएन सिंह ने कहा कि 5 दशक पहले गरीबों का भोजन कही जाने वाली मोटा अनाज आज अमीरों का भोजन कहा जाता है. वर्त्तमान में देश - विदेश के बाजारों में मोटे अनाज के उत्पाद काफी महंगी है और इसकी भारी मांग है. झारखण्ड राज्य में परंपरागत तौर पर मोटे अनाजों में मडुआ, गुन्दली, साँवा, कोदो और रामदाना की खेती प्रचलित थी. बाजार की मांग को देखते हुए किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित की जा सकती है. इसके लिए ग्रामीण स्तर पर मोटे अनाजों के प्रसंस्करण एवं मुल्यवर्धन तकनीकी को बढ़ावा समय की बड़ी मांग है. इस तकनीकी से मोटे अनाज का बाजार मूल्य को बढाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव होगी. उन्होंने कहा कि इस तकनीकी से व्यवसाय की शुरूआत लघु स्तर पर की जा सकती है. बाजार मांग के अनुरूप व्यवसाय का विस्तार की जा सकती है. ग्रामीणों के आय सृजन में यह महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है. मुख्य अतिथि आईसीएआर - भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआ-ईएबी), गढ़खटंगा, रांची के निदेशक डॉ ए पट्टनायक ने राज्य में मोटे अनाज में मडुआ की खेती और इसके उत्पादों की संभावना पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन में प्रसंस्करण एवं मुल्यवर्धन का समावेश जरूरी हो गया है. राज्य में अधिक उपज देने वाली सफ़ेद मडुआ प्रभेद की खेती की काफी संभावना है. मडुआ के साथ राजमा/सोयाबीन की अंतरवर्ती खेती लाभदायक होगी. उन्होंने कहा कि व्यावसायिक मानसिकता वाले प्रि-शिक्षाणार्थी गाँवों में समुह बनाकर व्यवसाय शुरू कर सकते है. आईआईएबी संस्थान इन समुहों प्रसंस्करण उपकरण मुहैया करायेगा. जिससे गाँवों में कुटीर उद्योग की स्थापना को बल मिलेगा और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी होगी.मौके पर प्रशिक्षण के सभी 20 महिला प्रतिभागियों को बीएयू कुलपति एवं आईआईएबी निदेशक ने प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया.

प्रशिक्षण के कोर्स कोऑर्डिनेटर एवं सामुदायिक विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ रेखा सिन्हा ने कहा कि देश में कृषि उत्पादों का 10 प्रतिशत मात्र ही प्रसंस्कृत होता है, जबकि विदेशों में 60-70 प्रतिशत तक होता है. पोष्टिक फसलों की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित एवं बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को गति दी जा सकती है.

डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव, डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद, डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉ जगरनाथ उराँव एवं आईआ-ईएबी के प्रधान वैज्ञानिक डॉ विनय कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये.

प्रतिभागियों में कोयली टोप्पो ने मडुआ एवं अन्य फसलों के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की जानकारी को ग्रामीण महिलाओं हेतु बेहद बताया. सरिता खलको ने प्रसंस्करण एवं मुल्यवर्धन सबंधित व्यावहारिक तकनीकी को ग्रामीण कुटीर व्यवसाय हेतु सरल माध्यम एवं लाभकारी बताया. समा-रोह का संचालन हरियाली रेडियो की समन्यवयक शशि सिंह ने की. धन्यवाद आ-ईआईएबी के वैज्ञानिक डॉ अविनाश पांडे ने दी. मौके पर डॉ डीके शाही, डॉ पीके सिंह, डॉ वी लकड़ा, डॉ एम चक्रवर्ती, डॉ बन्धनु उराँव, एचएन दास, बसंती कोंगाडी एवं स्मिता स्वेता आदि मौजूद थे.

जेएएमटीटीसी के प्रशिक्षाणार्थियों ने कृषि यंत्र तकनीकों को जाना

रांची के झारखण्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी टूल्स ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित 30 दिवसीय प्रशिक्षण के 20 डिप्लोमाधारी प्रि-शिक्षाणार्थियों ने बीएयू के कृषि अभियंत्रण विभाग का भ्रमण किया. इन प्रशिक्षाणार्थियों को विभागाध्यक्ष ई डीके रूसिया ने उन्नत कृषि यंत्रो की तकनीकी, उपयोगिता एवं कार्य क्षमता की जानकारी दी. मौके पर सहायक प्राध्यापक ई गौरव साहु ने कृषि यंत्र संग्रहालय में मौजूद कृषि यंत्रो की प्रौद्योगिकी तकनीक की व्यावहारिक जानकारी दी.

प्रशिक्षाणार्थियों में चतरा, रामगढ, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा एवं दुमका जिलो के डिप्लोमाधारी अभियंत्रक शामिल थे. धनबाद के राजकुमार ने कृषि यंत्रो की व्यवहारी जानकारी को जिला स्तर पर कृषि गतिविधियों के कार्यान्वयन में मददगार होने की बात कही।

सीसीएल में 'स्वच्छता शपथ' के साथ 'स्वच्छता माह 2021' का शुभारंभ

संवाददाता :

''स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत'' के संदेश के साथ सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 'स्वच्छता माह, 2021' मनाया जा रहा है । स्वच्छता माह का प्रारंभ सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में 'स्वच्छता शपथ' समारोह का आयोजन कर इसका शुभारंभ किया गया। सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने उपस्थित सभी कर्मियों को ''स्वच्छता की शपथ' दिलायी। इस अवसर पर सीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास-तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह सहित सीसीएल के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष तथा सीसीएल कर्मी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।

सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपिता के सपनों को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा देश स्वच्छ, स्वस्थ्य और विकसित हो सके। भोला प्रसाद ने कहा कि 'स-वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' के निर्माण में हमारा नैतिक कतर्व्य बनता है कि जहाँ हम रहते हैं, कार्य करते हैं, उस जगह को साफ एवं स्वच्छ रखें और इसके लिए दूसरों को भी अवश्य प्रोत्साहित करे। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार ने किया। साथ ही इस आयोजन में विभागाध्यक्ष (सीएसआर) एस.एस. लाल एवं उनकी टीम के सक्रिय सहयोग रहा।

सीसीएल में बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता पर हुआ सेमिनार

संवाददाता

रांची : IIT (ISM) पूर्व विद्यार्थी संघ मुख्य शाखा और रांची अध्-याय के तत्वावधान में 2 अक्टूबर, 2021 को कन्वेंशन सेंटर, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची में बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए खनन और तेल और गैस क्षेत्रों में डिजिटल नवाचारों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञों को शामिल करते हुए खनन और तेल और गैस क्षेत्रों में स्थायी संचालन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता बिनय दयाल और इस संगोष्ठी की आयोजन समिति के अध्यक्ष ने की, जिन्होंने वृद्धिशील के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय लांदुपडीह में वृक्षारोपण कार्यक्रम

राँची/सोनाहातू : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय लांदुपडीह में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । प्रभारी प्रधानाध्यापक दुलाल चन्द्र महतो एवं झारखंड +2 शिक्षक संघ, रांची जिला, अध्यक्ष संतोष कुमार महतो की देख-रेख में यह कार्यक्रम किया गया। वन एवं पर्यावरण के प्रति छात्र एवं छात्राओं को जागरूक किया गया । इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में रूबेल लकड़ा, सुनील कुमार ,ज्योति कुजुर, डॉक्टर भास्कर ,डॉक्टर सोमनाथ, पंकज कुमार मेहता, बिंदेश्वर महतो , दिलीप कुमार महतो,पितांबर महतो, उमाकांत स्वांसी,विवेक कुमार महतो ,शंकर यादव तथा शिव प्रसाद महतो आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

सीएमडी सीएमपीडीआई विनय दयाल ने स्वच्छता शपथ दिलायी

संवाददाता रांची : सीएमपीडीआई में स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक स्वच्छता माह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यालय सहित इसके सभी क्षेत्रीय संस्थान में स्वच्छता माह मनाया जाएगा। स्वच्छता माह की शुरूआत सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विनय दयाल ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान-3 के कर्मियों को स्वच्छता शपथ दिलाकर की। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी)आर0एन0 झा, निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) ए0के0 राणा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी/ईएस) एस0के0 गोमास्ता, महाप्रबंधक (समन्वय) मनोज कुमार उपस्थित थे।

दर्शक दीर्घा और खिलाडी शयनागर के विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास

संवाददाता रांची : हटिया स्थित ऐस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में दर्शक दीर्घा एवम खिलाडी शयनागर के विस्तारीकरण के कार्य का शिलान्यास द.पू.रेलवे महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने किया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी महिला हॉकी मैच भी खेला गया। इसके बाद महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं मुख्य संरक्षक सेरसा (रएफ्रअ) द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक महोदया ने कहा रांची रेल मंडल में बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं विशेषकर हॉकी के क्षेत्र में रांची रेल मंडल के कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टीमों में अपनी जगह बनाई है। मैं सभी खिलाड़ियों से आह्वान करती हूं कि वह भारतीय रेल से जुड़े तथा भारतीय रेल द्वारा प्रदान किए गए सुविधाओं का लाभ उठाएं एवं अपने खेल कौशल का विकास करें तथा देश का एवं भारतीय रेल का मान बढ़ाएं । मैं आशा करती हूं स्टेडियम के विस्तारीकरण के बाद अगले ओलंपिक में खिलाड़ियों की संख्या अवश्य बढ़ेगी तथा देश, भारतीय रेल एवं दक्षिण पूर्व रेलवे का नाम और रोशन होगा। इसके पश्चात उन्होंने हटिया में स्काउट तथा गाइड द्वारा आयोजित स्वच्छता जागरूकता रैली को झण्डा दिखाकर रवाना किया। उन्होने पर्यावरण संबंधी कार्यों का और साथ ही हटिया स्टेशन पर कंबाइंड क्रू एवं गार्ड लॉबी तथा रनिंग रूम का भी निरीक्षण किया ।

इस मौके पर दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय से प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक प्रभास दंसाना, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सतीश पी दूधे , प्रधान मुख्य अभियंता यू के वरीन, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता पी के मंडल, प्रधान वित्त सलाहकार एवं अध्यक्ष सेरसा (रएफ्रअ) प्रशांत मिश्रा, मुख्य विद्युत लोकोमोटिव अभियंता आर के तिवारी, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी नीरज कुमार, महाप्रबंधक के सचिव वी के गुप्ता, रांची रेल मण्डल के अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (परिचालन) एम एम पंडित , अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (इन्फ्रा) सतीश कुमार , वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक सह मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अवनीश एवं सभी शाखा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दक्षिण पूर्व रेलवे ने गाँधी जयंती पर चलाया स्वच्छ भारत अभियान

संवाददाता

दक्षिण पूर्व रेलवे ने महात्मा गाँधी के 152वें जन्म दिवस को स्मरण करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा स्टेशन (न्यू कॉमप्लेक्स) के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर व्यापक श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। अतुल्य सिन्हा, अपर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे के दिशानिर्देश में हावड़ा स्टेशन (न्यू कॉमप्लेक्स) में स्वच्छ भारत अभियान का संचालन किया गया। मुख्य पर्यावरण अभियंता शैवाल बोस, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मियों, दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों, आरपीएफ कर्मियों इत्यादि ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया तथा श्रमदान किया। स्वच्छता को बरकरार रखने के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों ने एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया।

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा 16 सितम्बर, 2021 से ''स्वच्छता पखवाड़ा'' का आयोजन किया, जिसका आज (2 अक्टूबर, 2021) समापन हुआ। ''स्वच्छता पखवाड़ा'' के दौरान शपथ ग्रहण समारोह, पौधा रोपण, स्टेशनों पर जल की शुद्धता जांच, जागरुकता अभियान, वेबीनार, एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन इत्यादि जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय में चित्रांकन, स्लोगन लेखन तथा निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग की सुदीप्ता चट्टोपाध्याय ने चित्रांकन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार हासिल की, जबकि कार्मिक विभाग के शिवनाथ बंद्योपाध्याय ने निबंध लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यांत्रिक विभाग के अविनाश कुमार दास तथा भंडार विभाग के एम श्रीकांत ने अंग्रेजी तथा हिन्दी स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम स्थान अर्जित किया।

देश के 707 जिला अस्पतालों में से एक भी मानकों पर खरा नहीं उतरा

नीति आयोग ने पहली बार देश के जिला अस्पतालों के परफॉरमेंस का आकलन कर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की

सरकार के थिंक-टैंक नीति आयोग ने 30 सितंबर को देश के जिला अस्पतालों के प्रदर्शन के पहले अध्ययन की रिपोर्ट जारी की। "रिपोर्ट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल" के इस अध्ययन में देश के 707 जिला अस्पतालों को 10 प्रमुख मानकों पर परखा गया। यह अध्ययन 2017-18 के आंकड़ों पर आधारित है।

इस अध्ययन के लिए जिला अस्पतालों को तीन श्रेणियों में बांटा गया। छोटे अस्पताल (200 या इससे कम बेड वाले), मध्यम आकार के (201 से 300 बेड वाले) और बड़े अस्पताल (300 से ज्यादा बेड वाले)। इन कुल अस्पतालों में 62 फीसदी छोटे अस्पताल थे।

अध्ययन की प्रमुख बातें

औसतन एक जिला अस्पताल में हर एक लाख आबादी पर 24 बेड हैं। अध्ययन के लिए तय किया गया कि एक अस्पताल में प्रति एक लाख आबादी पर 22 बेड होने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, प्रति 1000 लोगों पर 5 बिस्तर होने चाहिए। अध्ययन में सामने आया कि अस्पताल में बेड का सबसे ज्यादा औसत पुडुचेरी में है, जबकि बिहार में यह औसत सबसे कम है। यहां प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 6 बेड हैं। कुल 707 जिला अस्पतालों में से सिर्फ 27 फीसदी में डॉक्टरों और बेड का अनुपात 29 पर 100 है। यानी इन अस्पतालों में हर 100 बेड पर 29 डॉक्टर उपलब्ध हैं।

707 में से 88 अस्पतलों में जरूरत के हिसाब से नर्स उपलब्ध हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस के मानकों के मुताबिक बेड कैटेगरी की बात करें तो 399 अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ तैनात दिखा। ऐसे अस्पताल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में (14.8%), फिर दिल्ली में (12.5%) और इसे के बाद उत्तर प्रदेश (11.4%) में मिले। देश के हर जिला अस्पताल में औसत 11 सपोर्ट सर्विस हैं, जबकि इनकी संख्या 14 होनी चाहिए। सिर्फ 89 अस्पताल सभी सपोर्ट सर्विस होने के मापदंड पर खरे उतरे। इन अस्पतालों में से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में (20.2%), फिर राजस्थान (11.2%), उत्तर प्रदेश (10.1%), कर्नाटक (10.1%) और पश्चिम बंगाल (9%) में मिले। 21 अस्पतालों ने सभी डायग्नोस्टिक सर्विस उपलब्ध होने के मानदंड को पूरा किया। कर्नाटक के पास सबसे ज्यादा 28.6% ऐसे अस्पताल थे। इसके बाद तेलंगाना में 19%, आंध्र प्रदेश में 14% और गुजरात में 9.5% ऐसे अस्पताल मिले। 707 में से 182 अस्पतालों में 90 फीसदी से ज्यादा बेड भरे थे। 80 से 85 फीसदी तक बेड भरे होना आदर्श माना जाता है। यूपी में 14.8% अस्पतालों में 90 फीसदी या उससे अधिक बेड भरे थे। मध्य प्रदेश में 10.9%, महाराष्ट्र में 8.2%, पश्चिम बंगाल में 7.1% और आंध्र प्रदेश में 5.5% अस्पतालों में 90 फीसदी या उससे ज्यादा बेड भरे थे।

अध्ययन के मुताबिक औसतन एक जिला अस्पताल में एक डॉक्टर 27 मरीजों को देखता है।

साभार : डीटीइ

जल के खतरनाक तत्वों से आंध्र के तटीय इलाकों में किडनी रोग बढने का अंदेशा

आंध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्र में चालीस वर्ष तक के वयस्कों में किडनी रोगी ज्यादा हैं

कन्हैया लाल

आंध्र प्रदेश-श्रीकाकुलम जिले में लगभग दो सौ वर्ग किलोमीटर के समुद्रतटीय क्षेत्र में बसे कई गांव पिछले तीन दशकों से एक रहस्यमय किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। यह बीमारी गरीब कृषकों में मुख्यरूप से व्याप्त है और चिकित्सा जगत के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसे चिकित्सीय भाषा में क्रोनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन नाम दिया गया है। इस बीमारी में दोनों किडनी सिकुड़ कर छोटी होती जाती हैं और कुछ ही वर्षों में बिल्कुल खराब हो जाती हैं। ऐसी बीमारी सामान्यतः साठ वर्ष से ज्यादा उम्र के उन लोगों में होती है जो कि पांच-दस वर्षों से डायबिटीज और हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) की समस्या से ग्रसित होते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश के इस समुद्रतटीय क्षेत्र में इस बीमारी का फैलाव चालीस वर्ष तक के वयस्कों में ज्यादा है और इन लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या भी नही है।

इस रहस्यमयी किडनी की बीमारी को पर्यावरण प्रदूषण के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है, हालांकि ये तथ्य अब तक वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं है। दूषित पानी, भोजन, मिट्टी और हवा में मौजूद कुछ खास प्रदूषक इस बीमारी के मूल कारण हो सकते हैं। पिछले दो वर्षों में टेरी ने आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र में पर्यावण प्रदूषण का व्यापक मूल्यांकन किया। भूजल इस क्षेत्र में पीने के पानी का मुख्य स्रोत है कुछ वर्ष पहले तक यहां अधिकांश लोग कुएं और हैंड पंप का पानी पीते थे। अब इस क्षेत्र में आरओ शोधित जल भी उपलब्ध है। टेरी टीम ने इस क्षेत्र के चालीस गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच की। यहां जल असामान्य रूप से अम्लीय पाया गया।

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक के अनुसार पेयजल का pH 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए । इस अम्लीय भूजल में सिलिका और लेड के मात्रा भी असामान्य मात्रा में मापी गई। सामान्यतः पेयजल में सिलिका की मात्रा 25 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है। जबकि पेयजल में लेड की मात्रा विश्व स्वास्थ संगठन के मानकों के अनुसार 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए एक मिली ग्राम एक ग्राम का हजारवां और एक माइक्रोग्राम दस लाखवां भाग होता है। सिलिका पर्यावरण में रेत के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सिलिका नॉनटॉक्सिक पदार्थ है, हालांकि हाल के शोध में पेयजल में 40 मिलीग्राम प्रतिलीटर से अधिक सिलिका किडनी सेल के लिए हानिकारक पायी गयी है। वहीं लेड यानी सीसा का मानव स्वास्थ पर कई हानिकारक प्रभाव हैं। लेड की तय मानक से अधिक मात्रा शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी, किडनी और दिमागी रोगों को न्योता देती है। हाल के चिकित्सा अनुसंधान में सिलिका और लेड का जुड़ाव क्रोनिक किडनी रोगों में पाया गया है और इस विषय पर गहन अनुसंधान की तत्काल आवश्यकता है।

अप्रत्याशित रूप से भूजल में थैलेट्स - जो कि प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए डाले जाते हैं, परीक्षण किए गए सभी पानी के सैंपल में उपस्थित थे। थैलेट्स का जुड़ाव इस तरह के किडनी रोग में अब तक स्थापित सत्य नही और इस दृष्टि से भी रिसर्च की जरूरत है। टेरी टीम ने किडनी बीमारी से ग्रसित इस क्षेत्र में मिट्टी का व्यापक परीक्षण किया। धान यहां की मुख्य फसल है। हरी सब्जियों की खेती भी होती है। जबकि काजू और नारियल व्यापार की दृष्टि के महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन क्षेत्र के सभी चालीस गांवों से मिट्टी के पांच-पांच सैंपल इन तीनों तरह की फसलों के खेतों से लिये गए और परीक्षण में भारी धातुओं जैसे लेड, क्रोमियम, निकल आदि की उपस्थिति जांची गयी। सब्जियों के खेत से लिये गए मिट्टी के सैम्पल में भारी धातुओं की मात्रा सबसे ज्यादा थी और काजू के जंगल से ली गयी मिट्टी में भारी धातुओं की मात्रा सबसे कम थी। यह निष्कर्ष भारी धातुओं का स्रोत पता करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्रोमियम इस क्षेत्र की महेन्द्रतान्या नदी के पानी में भी पाया गया । जबकि यहां प्रयोग किये जा रहे उर्वरक (फर्टिलाइजर) जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश में भी भारी धातुएं पायी गयीं ।इन उर्वरकों और सिंचाई के जल के लगातार प्रयोग से मिट्टी में भारी धातुओं की मात्रा बढ़ना अपेक्षित है। हालांकि जंगल की मिट्टी में भी भारी धातुओं का उपस्थित होना दर्शाता है कि ये धातुएं यहां की मिट्टी में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में हैं।

पीडीएस में मिलने वाले चावल यहां के निम्न आय वाले किसानों का मुख्य भोजन है। समुद्र तट के अति समीप बसे गांवों में सूखी मछलियां भी भोजन में सामान्यतः सम्मिलित होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और चौलाई थोड़ी मात्रा में पूरे साल खाई जाती हैं। इन चावल के सैंपल में भी भारी धातुएं मुख्यतः लेड 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से ज्यादा पाई गई। लेड की इतनी मात्रा चावल के माध्यम में शरीर में पहुंचना किडनी के लिए घातक हो सकता है। मछली और सब्जी के सैंपल में भी इसी तरह के परिणाम प्राप्त हुए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में पैदा हुए धान, उड़द, तिल के सैंपल भी जांचे गए और भारी धातुओं की उपस्थिति जांचे गए सभी प्रकार के सैंपल में मिले तुलनात्मक अध्ययन के लिए आंध्र प्रदेश के नौ और जिलों - विजयनगरम, विशाखापट्नम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम, कृष्णा, नेल्लोर और कड़पा के दस-बीस चिन्हित गांवों से भूजल, मिट्टी और चावल के सैंपल जांचे गए। अम्लीय जल में उच्च सिलिका और लेड केवल में श्रीकाकुलम के किडनी बीमारी ग्रसित क्षेत्र में ही मिले जबकि मिट्टी और चावल में लेड सभी जिलों से लिये गए सैंपल में पाए गए।

लेखक इस अध्ययन से जुड़े हैं यह अध्ययन इंडियन कॉउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की एक चिकित्सा टीम-द जॉर्ज इंस्टिट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के साथ किया गया।

मध्यप्रदेश में बाघों को बचाने के लिये चाहिये हाथी

मनीष चंद्र मिश्र

बाघ संरक्षण में हाथियों की जरूरत होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उमेश कुमार शर्मा बताते हैं कि गश्ती के लिए हाथी बहुत जरूरी है, विशेषकर मानसून में। जंगल के कुछ हिस्सों में वाहन से जाना संभव नहीं है।वहां हाथी ही एकमात्र साधन हैं। गश्ती के अलावा बाघों के इलाज, रेडियो कॉलर लगाने हेतु बाघ को बेहोश करने के लिए हाथी की जरूरत होती है।

मध्य प्रदेश वन विभाग के पास 50 से अधिक पालतू हाथी हैं जिसमें से तकरीबन 35 ही गश्ती और अन्य कामों के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। बचे हुए या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग। प्रदेश में वन क्षेत्र और टाइगर रिजर्व में बढ़ते बाघों की संख्या को देखते हुए कम से कम 50 हाथियों की जरूरत है। मध्य प्रदेश का वन विभाग इस कमी को पूरा करने के लिए कर्नाटक, राजस्थान, अंडमान सहित कई स्थानों से हाथी लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, एक दशक से चल रही कोशिशों में अब तक नाकामी ही हाथ लगी है।

पालतू हाथी का बाघ संरक्षण में काफी योगदान है। हालांकि, पालतू हाथियों की खराब स्थिति को लेकर देश में बहस चली हुई है, जिसकी वजह से जानकार हाथी का विकल्प खोजने पर जोर देते हैं। इस साल जनवरी में एक बाघ मध्य प्रदेश के हरदा जिले स्थित केलझिरी वन के एक गांव में घुस आया। तीन दिन में ही बाघ ने इंसानों पर तीन बार हमले किए जिसमें एक की मौत हो गई। ग्रामीण भी बाघ के खून के प्यासे हो गए। वन विभाग का रेस्क्यू दल गांव और जंगल की खाक छानता रहा। ड्रोन की भी मदद ली गई। पर बाघ पकड़ में नहीं आया।

वन विभाग के अमले को एक अदद हाथी की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। पर कोई हाथी मौजूद नहीं था। आनन-फानन में वन विभाग को करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से हाथी मंगाना पड़ा। हाथी को ट्रक में लादकर, पूरे दिन थका देने वाली यात्रा के बाद, हरदा लाया गया। तब जाकर बाघ रेस्क्यू हुआ। ऐसा ही एक मामला 2019 में सामने आया जब भोपाल के वन क्षेत्र में हाथी की सख्त जरूरत महसूस हुई। एक घायल बाघ को बचाने के लिए वन विभाग के अमले को भोपाल के कठिन जंगलों के बीच जाना था। यह काम हाथी के बिना नहीं हो सकता था, सो 130 किलोमीटर दूर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से हाथी मंगाए गए।

इन घटनाओं से बाघ संरक्षण में हाथियों की अहम भूमिका का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें हाथियों की कमी खलती है। प्रदेश को 2018 में हुए बाघ गणना के आधार पर टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। इस गणना में यहां 526 बाघ पाए गए थे। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी की मदद से गश्ती करते वनकर्मी। तस्वीर- टीआर शंकर रमन/विकिमीडिया कॉमन्स

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी की मदद से गश्त लगाते वनकर्मी। तस्वीरझ टीआर शंकर रमन/विकिमीडिया कॉमन्स

मध्य प्रदेश में जरूरत के मुताबिक पालतू हाथी या बंधक बनाए गए हाथी नहीं हैं। इससे बाघ संरक्षण के काम में दिक्कत आती है। वन विभाग के मुताबिक प्रदेश में 52 पालतू हाथी वन विभाग के पास हैं जिसमें से महज 35 ही काम करने लायक हैं। बाकी या तो बुजुर्ग हैं या बच्चे जिनसे काम नहीं लिया जा सकता।

भोपाल के आसपास इस वक्त 18 बाघ घूम रहे हैं, जिसमें से छह बाघ तो सीमा के भीतर घुस आए हैं। समय समय पर वन विभाग, गश्त के जरिए, बाघों को आबादी से दूर रखने की कोशिश करता रहता है। ऐसे समय में हाथी की जरूरत महसूस होती है। बाघ का रेस्क्यू हाथी के बिना संभव ही नहीं लगता,'' भोपाल के पूर्व मुख्य वन संरक्षण एसपी तिवारी कहते हैं कि हाथी बाहर से मंगाना एक महंगा सौदा है। इसमें न सिर्फ पैसे अधिक खर्च होते हैं, बल्कि हाथी को अधिक थकान भी होती है। ऊपर से महावत भोपाल के जंगल से परिचित नहीं होते जिससे काफी दिक्कतें आती हैं,'' वह कहते हैं। बाघों की गतिविधियों को देखते हुए, इनके अनुसार भोपाल में कम से कम दो हाथी होने चाहिए।

वायु प्रदूषण से 59 लाख बच्चे असमय जन्मे

दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण के चलते करीब 59 लाख नवजातों का जन्म समय से पहले हो जाता है जबकि करीब 28 लाख शिशुओं का वजन जन्म के समय सामान्य से कम होता है

दुनिया भर में हर साल करीब 59 लाख नवजातों का जन्म वायु प्रदूषण के चलते समय से पहले ही हो जाता है। यही नहीं वायु प्रदूषण के चलते जन्म के समय करीब 28 लाख नवजातों का वजन सामान्य से कम होता है। गौरतलब है कि एक सामान्य बच्चे का वजन जन्म के समय ढाई किलोग्राम या उससे ज्यादा होता है। यह जानकारी हाल ही में राकेश घोष के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा किए शोध में सामने आई है, जोकि 28 सितम्बर 2021 को जर्नल प्लोस मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। इस शोध में शोधकर्ताओं ने घर के भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद वायु प्रदूषण के प्रभाव का विश्लेषण किया है।

यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों को देखें तो हर वर्ष जन्म लेने वाले करीब 2 करोड़ नवजात बच्चों का वजन जन्म के समय सामान्य से कम होता है। वहीं करीब 1.5 करोड़ बच्चों का जन्म समय से पूर्व ही हो जाता है। वहीं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) 2019 के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के 34 फीसदी बच्चों की मौत के लिए जन्म के समय कम वजन जिम्मेवार था, जबकि इसी आयु वर्ग के करीब 29 फीसदी बच्चों की मौत के लिए उनका समय से पूर्व जन्म लेना वजह था। इस शोध में घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण को भी शामिल किया गया है, जो ज्यादातर लकड़ी, कोयले और कंडों से चलने वाले चूल्हों के कारण होता है। अनुमान है कि यह इस समस्या के करीब दो-तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेवार है।

खुले में शौच करते हैं दुनिया के 49.4 करोड़ लोग

एजेंसियां: 2015 में देश की करीब 40 फीसदी ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा घटकर 22 फीसदी रह गया

इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले पांच वर्षों में 2015 से 2020 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। पर इस-ाके बावजूद अभी भी दुनिया भर में करीब 49.4 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं, जिसमें भारत की भी करीब 15 फीसदी आबादी शामिल है। यदि देखा जाए तो दुनिया के 55 देशों में अभी भी 5 फीसदी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करती है। जहां उप सहारा अफ्रीका में स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। हालांकि देखा जाए तो 2015 से 2020 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में करीब 24.5 करोड़ की गिरावट आई है। जो काफी हद तक मध्य और दक्षिण एशिया की वजह से संभव हो पाया है। जहां पिछले पांच वर्षों में खुले में शौच करने वालों की संख्या में 19.6 करोड़ की कमी आई है, इसमें एक बड़ी आबादी भारत की भी है। यही नहीं जहां पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसकी संख्या में 2.4 करोड़ की कमी आई है वहीं दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन में यह कमी करीब एक करोड़ दर्ज की गई है। देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश क्षेत्र 2030 तक खुले में शौच करने की कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की राह पर हैं। इस मामले में उप-सहारा अफ्रीका बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जबकि ओशिनिया में खुले में शौच की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी हाल ही में डब्लूएचओ और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट 'प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन 2000-2020' नामक रिपोर्ट में सामने आई है।

अफ्रीका में दक्षिण सूडान, चाड और नाइजर ऐसे देश हैं जहां अभी भी 60 फीसदी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, गाम्बिया, मायोट, रीयूनियन, सैंटो हेलेना, सेशेल्स जैसे देश हैं जहां कि एक फीसदी से भी कम आबादी खुले में शौच करती है।

अवशेषों से होगा हाइड्रोजन का उत्पादन

मुकेश रंजन

कृषि अवशेषों का उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में किया जा सकता है, यह ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट निपटान दोनों समस्याओं को हल कर सकता है।

भारतीय शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के सीधे उत्पादन के लिए एक अनूठी तकनीक विकसित की है। शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह नया प्रयोग हाइड्रोजन उपलब्धता की चुनौती से पार पाने में मदद कर सकता है। पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन-सेल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है। भारत ने 2030 तक लगभग 450 गीगावाट यानी 60 फीसदी अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। वर्तमान परिदृश्य में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, शोधकर्ता अक्षय ऊर्जा समाधानों की दिशा में काम कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा कार्बन को सीमित करने वाली होनी चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने के सबसे किफायती तरीकों में से एक सस्ते, प्रचुर मात्रा में और अक्षय स्रोत से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

कृषि अवशेषों या अपशिष्ट, जिसके निपटान के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसका उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जा सकता है सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट निपटान की दोनों समस्याओं को हल कर सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने के पीआईटी टेक्नोलॉजीज की संवेदनशील प्रयोगशालाओं के सहयोग से कृषि अवशेषों से हा-इड्रोजन निकालने के लिए प्रयोगशाला स्तर पर इस तकनीक को विकसित किया है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि मौजूदा इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में हमारी तकनीक 25 फीसदी अधिक कुशल है। इस दो चरणों वाली प्रक्रिया में बायोमास के पहले उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह यह प्रक्रिया को किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। एप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल (एआरआई) के निदेशक डॉ प्रशांत ढाकेफलकर ने कहा यह प्रक्रिया पोषक तत्वों से भरपूर एक पदार्थ को उत्पन्न करती है जिसका उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम जिसमें एमएसीएस-एआरआई के डॉ. एस.एस. डागर और प्रणव क्षीरसागर और केपीआईटी-सेंटएंट के श्री कौस्तुभ पाठक ने इस प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तकनीक को विकसित करने वालों ने बताया कि हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन प्रक्रिया में एक विशेष रूप से विकसित माइक्रोबियल कंसोर्टियम का उपयोग शामिल है जो सेल्यूलोज के बायोडिग्रेडेशन की सुविधा प्रदान करता है। तत्पश्चात हेमिकेलुलोज से परिपूर्ण कृषि अवशेष, जैसे कि धान, गेहूं, या मक्का के बायोमास, बिना थर्मो-केमिकल या एंजाइमेटिक प्रिट्रीटमेंट के इसमें शामिल किए जाते हैं।प्रक्रिया पहले चरण में हाइड्रोजन और दूसरे में मीथेन उत्पन्न करती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न मीथेन का उपयोग अतिरिक्त हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। सेंटियंट लैब्स के अध्यक्ष रवि पंडित ने कहा कि उपयोग न होने वाले कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने की यह सफलता हमें ऊर्जा संसाधनों पर आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। यह किसान समुदाय को राजस्व की एक बड़ी धारा भी जोड़ेगा।

टकले होने से बचना है तो कम खाएं वसा युक्त भोजन

शोधकर्ताओं ने पाया कि मोटापे की वजह से हेयर फॉलिकल स्टेम सेल (एचएफएससी) की कमी हो सकती है, जिससे दोबारा उगना बंद हो जाते हैं

यह लगभग सभी जानते हैं कि मोटापा इंसानों में कई बीमारियों को बढ़ता है। मोटे व्यक्तियों में हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियां बेहद आम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक दुनिया भर में सन 2000 तक मोटापे से ग्रसित वयस्कों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ से अधिक हो गई है।विकासशील देशों में लगभग 11.5 करोड़ से अधिक लोग मोटापे से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि शरीर के अंग विशेष रूप से कैसे खराब होते हैं और लगातार चले आ रहे या पुराने मोटापे से कार्यक्षमता कैसे कम होती है।

टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी (टीएमडीयू) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने माउस मॉडल प्रयोगों का उपयोग अधिक वसा और बालों के झड़ने के बीच संबंध का पता लगाने के लिए किया है। उन्होंने इस बात की जांच की कि क्या खाने में अधिक वसा का उपयोग या आनुवंशिक रूप से होने वाले मोटापे के चलते बालों के पतले होने और झड़ने को किस तरह प्रभावित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मोटापे की वजह से कुछ उत्तेजक संकेतों के शामिल होने से हेयर फॉलिकल स्टेम सेल (एचएफएससी) की कमी हो सकती है, जिससे बालों का पुनः उगना अवरुद्ध हो जाता है और अंततः बालों के रोम का नुकसान होता है। आम तौर पर, हेयर फॉलिकल स्टेम सेल (एचएफएससी) प्रत्येक बाल के रोम चक्र को स्वयं दोहराते हैं। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमारे बालों को लगातार बढ़ने देती है। मनुष्य की बढ़ती उम्र की वजह से, कम एचएफएससी या एचएफएससी खुद को फिर से भरने में विफल हो जाते हैं और इसलिए बाल पतले हो जाते हैं।

EZONECARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi

93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण से महासागरों पर दोहरी मार

प्लास्टिक के उत्पादन से 2015 से 2020 के बीच लगभग 5600 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने का अनुमान है।

प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को आमतौर पर दो अलग-अलग मुद्दों के रूप में देखा जाता है। अभी तक महासागर और यहां रहने वाली प्रजातियों पर प्लास्टिक प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव पर बहुत से शोध किए गए हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन पर भी अनगिनत शोध हुए हैं। लेकिन प्लास्टिक और जलवायु परिवर्तन एक साथ कैसे कार्य करते हैं, इसके मिश्रित प्रभावों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

अब अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में जलवायु संकट और प्लास्टिक प्रदूषण के बीच मूलभूत संबंधों का खुलासा किया है। चरम मौसम की घटनाओं के कारण माइक्रोप्लास्टिक दूर-दूर तक फैल जाता है। यह शोध जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन और बांगोर यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर किया गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार इस बात के सबूत जुटाए हैं कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। दोनो मिलकर खतरनाक चक्र बना रहे हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा सरकारों और नीति निर्माताओं को इन दो मुद्दों को एक साथ निपटाने का आग्रह किया जा रहा है। टीम ने तीन महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जिसमें जलवायु संकट और प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जैव विविधता के नुकसान से जुड़ा हुआ है। पहला यह है कि प्लास्टिक अपने पूरे जीवन चक्र में उत्पादन से लेकर निपटान तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) में कैसे योगदान देता है।

दूसरा यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े बाढ़ और आंधी जैसे चरम मौसम प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे फैलाएंगे और इसे बदतर करेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे महासागर, समुद्र और नदियों के लिए प्रमुख मुद्दे रहे हैं। तीसरा बिंदु समुद्री प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करता है जो विशेष रूप से दोनों की वजह से कमजोर पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री जैव विविधता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। जिसमें हर एक जीव द्वारा गलती से प्लास्टिक की थैलियों को निगलने से लेकर माइक्रोप्लास्टिक से प्रदूषित पूरे आवास तक शामिल हैं। दुनिया भर में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किए जाने वाले प्लास्टिक की मांग बढ़ती जा रही है। जिसके चलते प्लास्टिक के उत्पादन से 2015 से 2020 के बीच ग्रीनहाउस (जीएचजी) में लगभग 5600 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पूरे शेष कार्बन बजट का 10 से 13 फीसदी है।जलवायु में हो रहे बदलावों के चलते पहले से ही तूफान और बाढ़ सहित चरम मौसम की घटनाएं अधिक हो रही हैं, जो भूमि और समुद्र के बीच कचरे के फैलने को बढ़ा रहा है। इसके अलावा, समुद्री बर्फ माइक्रोप्लास्टिक के लिए एक जाल का काम करती है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है बर्फ के पिघलने पर प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है।

प्रोफेसर कोल्डवी ने कहा की जलवायु परिवर्तन निस्संदेह हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक खतरों में से एक है। साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण का वैश्विक प्रभाव भी पड़ रहा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर हमारे महासागर के सबसे गहरे हिस्सों तक प्लास्टिक फैला हुआ है। दोनों का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि महासागरीय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के साथ समुद्र के तापमान को गर्म करने और प्रवाल भित्तियों को विरंजन (ब्लीच) करना शामिल है। प्लास्टिक समुद्री आवासों और प्रजातियों के लिए घातक है। दोनों संकटों का मिश्रित प्रभाव अब समस्या को बढ़ा रहा है। यह बहस का मामला नहीं है कि कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, यह पहचानना है कि दो संकट आपस में जुड़े हुए हैं और इनके लिए संयुक्त समाधान की आवश्यकता है। अध्ययन से पता चलता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन कमजोर प्रजातियां और उनके आवासों पर प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हें समुद्री कछुओं और कोरल को भी प्लास्टिक प्रदूषण से खतरा है। इसमें कहा गया है कि इन कड़ियों, में हमारे प्र-ाकृतिक वातावरण में उनकी भूमिका और दोनों मुद्दे पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

बांगोर विश्वविद्यालय के हेलेन फोर्ड ने कहा चूंकि प्रवाल भित्तियां मेरे शोध का केंद्र बिंदु हैं, इसलिए मुझे प्रतिदिन याद दिलाया जाता है कि ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े पैमाने पर विरंजन के कारण इनकी मृत्यु हो रही है, वहीं प्लास्टिक प्रदूषण इन तनावग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक और खतरा है। अध्ययन से पता चलता है कि प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दोनों में पहले से ही लगातार बदलाव हो रहे हैं जो समुद्री जीवों को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य प्रणाली में सबसे छोटे तैरते जीवों से लेकर सबसे बड़े व्हेल तक को प्रभावित कर रहे हैं।

RUDS

Rural Urban Development Society

Rural and Urban Development Society is supporting Humanity first in feeding the strays of Ranchi.

We are currently feeding 200+ dogs in three locations in Ranchi i.e., Ratu Raod, Baniatu & Railway Colony.

"FEEDING HUMAN'S BEST FRIEND. THEY JUST LOVE AND NOT BITE."

CONTACT US, FOR FURTHER QUERIES & DETAILS

SWATI-9431526364

GPay 8789398613

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।